अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–12 अंक–190 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ गुरुवार 9 नवम्बर 2023 पृष्ठ – 4 मूल्य–3 रूपया

संक्षिप्त समाचार

कैंसर जागरूकता दिवस पर डा शारिक अकील का व्याख्यान

अलीगढ़। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हैल्थ सर्विस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा शारिक अकील ने कहा कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है इसकी पहचान करना. कैंसर के लक्षण ऐसे होते हैं कि इसकी जल्दी पहचान कर पाना ही मुश्किल है। कैंसर की पहचान, रोकथाम और इसके इलाज के लिए हर साल 7 नवंबर के दिन को 'नेशनल कैंसर जागरूकता दिवस'के रूप में मनाया जाता है। डा शारिक अकील ग्रीन क्रीसेंट स्कूल में आयोजित कैंसर जागरूकता कायक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 1.1 मिलियन नए कैंसर के मामले सामने आते हैं और इनमें से अधिकांश मामलों का पता तब चलता है जब बीमारी थर्ड स्टेज में पहुंच चुकी होती है। डा शारिक अकील ने कहा कि लाइफस्टाइल में सुधार, तम्बाकू से परहेज, शरीर का वजन मेंटेन रखने हेल्दी डाइट लेने, फिजिकल एक्टिविटी करने, शराब का सेवन न करने, पराबैंगनी विकिरण से बचने, बाहरी और आंतरिक वायु प्रदूषण के जोखिम को कम करने आदि से इससे बचने के खतरों को कम किया जा सकता है। उन्होंने कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों समय रहते इलाज के अलावा सड़क सुरक्षा उपायों के अलावा स्कूल और कालिज के छात्र–छात्राओं से मोबाइल का अनुचित प्रयोग और इससे होने वाले नुकसान पर भी प्रकाश डाला। स्कूल की प्रिंसिपल डा शीबा ने डा शारिक अकील का स्वागत किया।

डायल-112 की महिला कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सियासत तेज,

सपा नेता ने बीजेपी पर पोस्टर जरिए कसा तंज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सहायता डायल–112 सेवा में संविदा पर काम कर रहीं महिला कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर राजनीति गरमा गई है। इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला ने मुख्यमंत्री आवास के पास एक पोस्टर लगाया है। जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने पोस्टर के जरिए भाजपा के नारी शक्ति वंदन और उत्तर प्रदेश में बेटियों की स्थिति पर कटाक्ष किया है। बता दें कि अपनी बिभिन्न मांग को लेकर महिला कर्मी धरना दे रही थी। 112 सेवा में संविदा पर कार्य कर रही महिलाएं सीएम योगी से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाहती थी। लेकिन पुलिस ने उन्हे रोक लिया। अब धरना दे रही महिला कर्मियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि महिला कर्मियों ने आपातकाल सेवाओं को बाधित, सरकारी आदेश का उल्लंघन किया है। बिना अनुमति धरना देना जैसे मामले में केस दर्ज किया है।

ऊर्जा मंत्री ने किया ओटीएस का शुभारम्भ

ओटीएस में 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक 54 दिन मिलेगा लाभ

पूरे देश में अब तक छूट की सबसे बेमिसाल योजना

उपभोक्ता जितना जल्दी करायेगा रजिस्ट्रेशन, उतना ज्यादा मिलेगा लाभ : शर्मा

लखनऊ, (यूएनएस)। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को लखनऊ के कसमाण्डा हास्पिटल के पास 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र न्यू कैण्ट, सदर में बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में छूट हेतु एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस की शुरूआत की। इस दौरान उन्होंने योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं में सदर के रामदास हाता निवासी मीरा, बबली, जगदेवी वर्मा, राजेश मेहर को सम्मानित भी किया। उन्होंने नचचबस.वतह में उपभोक्ताओं द्वारा कराये गये पंजीकरण की प्रक्रिया को भी जांचा, जिसमें सदर निवासी माधुरी पाण्डेय, संजीव कुमार, नीरज यादव ने पंजीकरण करा चुके थे। ओटीएस लागू करने के लिए उपस्थित उपभोक्ताओं ने ऊर्जा मंत्री और प्रदेश की योगी सरकार की प्रशंसा की। उपभोक्ताओं ने कहा कि यह योजना बकाये के अधिभार से मुक्ति दिलायेगी।ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे देश में छूट की अब तक की सबसे बेमिसाल योजना विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लायी है। सभी उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अतिशीघ्र नचचबस.वतह में रजिस्ट्रेशन करा लें। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। ओटीएस योजना के प्रथम चरण में 08 नवम्बर से 30 नवम्बर तक उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज में शत–प्रतिशत छूट दी जा रही है। उपभोक्ता अपना बकाया एक बार में एकमुश्त या किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाईयों एवं निजी संस्थाओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर छूट का तोहफा दिया है। देश में पहली बार विद्युत चोरी के मामले में भी जुर्माने की राशि में छूट दी

जा रही है। राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट के लिए इसका 10 प्रतिशत जमा करना होगा। दण्ड स्वरूप यदि किसी उपभोक्ता की आरसी कट गयी हो तो जैसे ही योजना में पंजीकरण होगा वैसे ही आरसी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35 प्रतिशत जमा करने पर ऐसे मामले समाप्त हो जाएंगे। इसमें 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।योजना के तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को 30 नवम्बर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत–प्रतिशत की छूट मिलेगी और 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट 03 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 06 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 03 किलोवाट भार तक केवाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 03 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 03 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा 03 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 03 डिफाल्ट तथा 06 किश्तों के मामले में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को 31 मार्च तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट नचचबस.वतह पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है। उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट नचचबसण्वतह पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना को हर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए, जिससे सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय। बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क भी करें। विद्युत बिलों में संशोधन के लिए अपने–अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन करें।इस अवसर पर प्रबंधन निदेशक मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत, निदेशक वाणिज्य मध्यांचल योगेश कुमार, मुख्य अभियंता लेसा सिसगोमती रजत जुनेजा, अधीक्षण अभियन्ता मण्डल प्रथम आरपी केन, अधिशाषी अभियन्ता राजभवन डीकेडी द्विवेदी, उपखण्ड अधिकारी कैन्ट सौरभ चौधरी एवं अवर अभियंता कैन्ट अशोक कुमार के साथ बड़ी संख्या में उपभोक्ता और छावनी परिषद तथा छावनी बोर्ड के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

लालजी टंडन के बेटे और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आशुतोष का निधन, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जताया शोक

लखनऊ। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री व लखनऊ पूर्व से विधायक आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी का निधन हो गया। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आशुतोष टंडन योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रहे। उनके निधन की जानकारी आशुतोष टंडन के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी दी गई। साइट पर लिखा गया कि गोपाल भइया हम सबको छोड़ कर चले गये। आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी भाजपा के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश व बिहार के राज्यपाल रहे स्वर्गीय लालजी टंडन के पुत्र थे। लालजी टंडन यूपी में भाजपा के प्रमुख स्तंभ व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मित्र व सहयोगी थे।

उनके निधन पर देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं लखनऊ पूर्व के विधायक, आशुतोष टंडन उर्फ 'गोपालजी' के निधन से मुझे गहरा दुःख हुआ। उनका राजनीतिक जीवन लखनऊ वासियों की सेवा में समर्पित था।पार्टी को मज़बूती देने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दुःख की इस घड़ी में उनके शोकाकुल परिवार के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शान्ति!

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं लखनऊ पूर्व के विधायक, श्री आशुतोष टंडन उर्फ 'गोपालजी' के निधन से मुझे गहरा दुःख हुआ। उनका राजनीतिक जीवन लखनऊ वासियों की सेवा में समर्पित था।पार्टी को मज़बूती देने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सहकार से समृद्ध की उपलब्धियों में सहकारिता विभाग ए$ ग्रेड प्राप्त कर अव्वल

पीएम किसान समृद्ध केन्द्र के रूप में पैक्स को विकसित करने में भी यूपी देश में प्रथम स्थान पर : राठौर

लखनऊ। मुख्यमंत्री के स्तर से अनुश्रवण किये जाने हेतु विकसित सीएम डैशबोर्ड पर विभागीय पोर्टलों के इन्टीग्रेशन के माध्यम से विभागों द्वारा सेवाओं एवं योजनाओं परियोजनाओं के सम्बन्ध में सितम्बर में किये गये प्रदर्शन के आधार पर मासिक ग्रेडिंग की गयी है, जिसमें सहकारिता विभाग ए$ ग्रेड प्राप्त कर प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने देते हुए बताया कि समन्वित शिकायत निराकरण प्रणाली आईजीआरएस के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में सहकारिता विभाग प्रथम स्थान पर है। सहकार से समृद्ध के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर जेनरिक दवाओं की पहुँच के लिए जन औषधि केन्द्र के रूप में पैक्स को विकसित किया जा रहा है इससे ग्रामीण,ब्लाक स्तर पर सस्ती जेनरिक दवाइयां भी आम लोगों को उपलब्ध हो सकेगी और पैक्स को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेगें। प्रदेश में पैक्स स्तर पर जन औषधि केन्द्र स्थापित करने हेतु 876 आवेदन किये गये है जिसमें से 440 प्राथमिक अनुमोदन हो जाने के उपरान्त 111 में ड्रग लाइसेंस प्राप्त हो चुके है। देश में पैक्स स्तर पर जन औषधि केन्द्र स्थापित करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।श्री राठौर ने बताया कि देश में नव गठित 03 बहुराज्यीय सहकारी समितियां भारतीय बीज सहकारी समिति. राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति तथा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति गठित की गई। भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता लेने में यूपी प्रथम स्थान पर है। पीएम किसान समृद्धि केन्द्र पीएमकेएसके के रूप में पैक्स को विकसित करने में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। प्राथमिक सहकारी समितियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत ई–सेवाओं के बेहतर पहुँच के लिए पैक्स में कॉमन सेवा केन्द्र की स्थापना की जा रही है, जिसके बाद सीएससी द्वारा दी जाने वाली 300 से भी अधिक ई–सेवाएं अब पैक्स भी दे सकेंगी। देश में पैक्स को सीएससी के रूप में ऑनबोर्ड किये जाने में उप्र देश में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि किसानों एवं प्रदेश हित में सहकारिता विभाग गम्भीरता के साथ कार्य करते हुए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

डीएम से मिलीं समूह की महिलाएं,खुली बैठक में हुआ था कोटा आवंटन,

शासनादेश न मानकर दोबारा बैठक की कह रहे बात

बस्ती। जिले में कोटे की दुकान चयन को लेकर डीएम कार्यालय पर बरखा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पहुंची और डीएम को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि कोटे की दुकान चयन को लेकर एसडीएम रूधौली धमकी दे रहे हैं। मामला रूधौली तहसील के ग्राम सभा डड़वा पांडेय का है। स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष बरखा देवी सहित अन्य महिलाएं डीएम आंद्रावामसी से मिली हैं और बताया कि ग्राम सभा डड़वा पांडेय में कोटे की दुकान खाली है। ग्रामसभा की खुली बैठक 28 अगस्त को हुई थी, जिसमें बरखा स्वयं सहायता समूह को उचित दर की दुकान आवंटन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सभी कागजात पूर्ति निरीक्षक रूधौली को दिया गया था। बताया कि उनके द्वारा कहा गया कि शासनादेश के मुताबिक आरक्षण देते हुए स्वयं सहायता समूह को कोटे का आवंटन किया जाएगा। समूह की अध्यक्ष बरखा ने कहा कि ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव किया गया था कि बरखा स्वयं सहायता समूह को कोटे की दुकान का आवंटन कर दिया जाए। आरोप लगाते हुए कहती हैं कि कुछ समय बाद समूह ने अपने कागजात के बारे में पता किया तो उप जिलाधिकारी रूधौली ने धमकी दी कहा कि हम शासनादेश को नहीं मानते हैं फिर से ग्राम सभा की बैठक होगी तब जाकर कोटे का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सप्लाई इंस्पेक्टर व एसडीएम कुछ राशन माफियाओं के दबाव व प्रलोभन में आकर राशन की दुकान का आवंटन नहीं कर रहे हैं। किसी राशन माफिया के पक्ष में कोटे की दुकान का चयन करने के प्रयास में लगे हैं। इस दौरान ज्ञानमती, रंभा, सुनीता, अनीता, गीता, करोड़ा देवी, गायत्री, शांति देवी, उमा देवी, संगीता, रेखा, सुरेखा, जयदीप निषाद, धर्मराज निषाद, विद्या प्रकाश निषाद, संदीप, रामनवल, अखिल, अखिलेश सिंह अन्य निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

बीएसए पर मनमानी करने का आरोप,शिक्षक नेताओं ने डीएम को दिया ज्ञापन

बस्ती। जिले में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ बीएसए पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। जिसको लेकर शिक्षक संघ अध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल के नेतृत्व में संगठन से जुड़े शिक्षकों ने डीएम को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा और उनकी समस्याओं के निस्तारण करने की मांग की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में शासन व सचिव बेसिक शिक्षा के निर्देश के क्रम में वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है और पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। बस्ती में भी वरिष्ठता सूची अपलोड किया गया, लेकिन 68 हजार 500 और एमआरसी के अंतर्गत जो शिक्षक जनपद में कार्यरत हैं, ट्रांसफर होकर आए। उनका नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया गया। जबकि शासनादेश है कि 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में नाम शामिल होना चाहिए। सबसे पहले हमारी मांग यह है कि वरिष्ठता सूची में 68 हजार 500 शिक्षकों का नाम शामिल किया जाए। शिक्षक नेता कहा कि जिला बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा शासनादेश व नियमों का पालन नहीं किया जाता। कोई भी झूठी कम्पलेंट डाल दिया तो अध्यापकों का वेतन रोक दिया जाता है। इसके साथ ही निलंबन भी कर दिया जाता है। बीएसए मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि शासनादेश के अनुसार जब तक कर्मचारी और शिक्षक से स्पष्टीकरण न लिया जाए तब तक किसी के विरूद्ध कोई कार्रवाई न की जाए। जिला उपाध्यक्ष इंद्रसेन मिश्रा ने कहा कि आयुक्त व जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में अंर्तजनपदीय स्थानांतरण से आए शिक्षकों के वेतन व बकाया वेतन 15 सितंबर तक भुगतान किया जाना था, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। बकाए वेतन का भुगतान शीघ्र किया जाए। शिक्षकों व कर्मचारियों के महंगाई भत्ता व बोनस दीपावली के पूर्व भुगतान किए जाने का निर्देश है। जिसे शीघ्र किया जाए।

अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर एसडीएम की छापेमारी,शटर गिराकर भाग खड़े हुए संचालक

बस्ती। जिले में अल्ट्रासाउंड संचालकों में उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रशासनिक अमले ने अचानक से छापेमारी की कार्रवाई कर दी। कुछ सेंटर तो खुले मिले, जहां अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। कुछ तो अपने सेंटरों का शटर गिरकर भाग खड़े हुए। पुलिस बल को देख पहले तो हर कोई हैरान रह गया, लेकिन बाद में पता चला कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई की जा रही है। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल हुआ यूं कि एसडीएम सदर गुलाब चंद्र जिला महिला अस्पताल के सामने दल बल के साथ जब पहुंचे तो आस पास के लोग पहले तो समझ नहीं पाए कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन जब प्रशासनिक अमला अल्ट्रासाउंड सेंटरों के भीतर दाखिल हुआ तो लोगों को समझ आ गया कि जांच चल रही है। एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट का निर्देश है कि सभी अल्ट्रासाउंड मशीनों की चेंकिंग की जाए। इसकी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ अल्ट्रासाउंड मशीनें बिना दक्ष डॉक्टर के चलाई जा रही हैं। कुछ के संबंध में शिकायत है कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो डॉक्टर नामित हैं, वो बैठते नहीं हैं, उनके नाम से रजिस्ट्रेशन ले लिया गया है। एक डॉक्टर के नाम दस–दस रजिस्ट्रेशन हैं और वो डॉक्टर कभी रहते नहीं हैं, इन जगहों पर। थर्ड आदमी अल्ट्रासाउंड करता रहता है।

एसडीएम ने बताया कि महिला अस्पताल के सामने चार अल्ट्रासाउंड सेंटर चेक किए हैं, जहां एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिले हैं। डॉक्टर के न मिलने पर और देखा गया कि रजिस्टर में दो अल्ट्रासाउंड किया गया है। डॉक्टर से सीन भी नहीं है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि यहां पर डॉक्टर आते नहीं हैं। टीम के पहुंचने पर दो से तीन दर्जन अल्ट्रासाउंड संचालक ताला लगाकर फरार हो गए।

धान क्रय केन्द्रों का डीएम ने किया औचक निरीक्षण

बहराइच। जिले में धान क्रय का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तहसील महसी अन्तर्गत धान क्रय एजेन्सी यूपीएसएस, पीसीयू एवं पीसीएफ के 01–01 धान क्रय केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने क्रय केन्द्रों पर खरीद के लिए जरूरी संसाधनों, बोरों की उपलब्धता, धान की आवक, भुगतान तथा कृषकों की सुविधा हेतु की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने क्रय एजेन्सी यू. पी.एस.एस. के धान क्रय केन्द्र ललईबाग के निरीक्षण के दौरान क्रय केन्द्र पर ग्राम रमवापुर के कृषक पवन कुमार के धान की खरीद की जा रही थी। केन्द्र प्रभारी अमरिका प्रसाद ने बताया कि क्रय केन्द्र पर आने वाले यह पहले कृषक हैं। इनकी उपज लगभग 50 कुण्टल है। केन्द्र प्रभारी ने यह भी बताया कि उनके द्वारा क्षेत्र के लगभग 20 कृषकों से वार्ता की गई है। क्रय एजेन्सी पी.सी.यू. के धान क्रय केन्द्र गोपचन्दपुर के निरीक्षण के दौरान ग्राम गोपचन्दपुर के कृषक विक्रम प्रसाद द्वारा लाये गये लगभग 75 कुण्टल धान की खरीद की जा रही थी। केन्द्र प्रभारी अमरचन्द बाजपेई ने बताया कि इससे पूर्व ग्राम वीर सहायपुर के कृषक श्यामरंग से 19.70 कुण्टल धान की खरीद की गई है। श्री बाजपेई ने बताया कि क्षेत्र के लगभग 15 कृषकों से वार्ता की गई है। डीएम मोनिका रानी ने क्रय केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र के कृषकों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखें ताकि अधिक से अधिक धान की खरीद की जा सके। सभी क्रय केन्द्र धान खरीद हेतु शासन द्वारा भुगतान के सम्बन्ध में जारी 48 घण्टे की गाइडलाइन का कड़ाई के साथ अनुपालन करें। डीएम ने सचेत किया कि किसी भी क्रय केन्द्र पर किसानों का शोषण जैसी शिकायत के संज्ञान में आने पर क्रय केन्द्र प्रभारी के साथ–साथ जनपद के प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

खाण्डसारी शक्कर वितरण योजना हेतु 10920 लाख मंजूर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने वित्तीय वर्ष 2023–2024 में खाण्डसारी शक्कर वितरण योजना के लिए 10920 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिये हैं इस सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नयी मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

सम्पादकीय

अनेक समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी

भारत की आजादी के समय देश की आबादी 36 करोड़ थी, जो बढ़कर 143 करोड़ हो चुकी है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2024 तक भारत और चीन की जनसंख्या बराबर हो जाएगी और 2027 में भारत चीन को पछाड़कर विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा लेकिन भारत इसी साल दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को 'विश्व जनसंख्या दिवस' मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में देखें तो तेजी से बढ़ती आबादी के कारण ही हम सभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पहुंचाने में पिछड़ रहे हैं। बढ़ती आबादी की वजह से ही देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल हो चुकी है। हालांकि विगत दशकों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार जुटाने के कार्यक्रम चलाए गए लेकिन बढ़ती आबादी के कारण ये सभी कार्यक्रम 'ऊंट के मुंह में जीरा' ही साबित हुए। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही देश में आबादी और संसाधनों के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है। हकीकत यही है कि विगत दशकों में देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ी, उस गति से कोई भी सरकार जनता के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की व्यवस्था करने में सफल नहीं हो सकती थी।

आज देश की बहुत बड़ी आबादी निम्न स्तर का जीवन जीने को विवश है। देश में करीब 40 फीसदी आबादी आजादी के बाद से ही गरीबी के आलम में जी रही है। गरीबी में जीवन गुजार रहे ऐसे बहुत से लोगों की यही सोच रही है कि उनके यहां जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतने ही ज्यादा कमाने वाले हाथ होंगे किन्तु यह सोच वास्तविकता के धरातल से परे है। लगातार बढ़ती महंगाई के जमाने में परिवार बड़ा होने से कमाने वाले हाथ ज्यादा होने पर जितनी आय बढ़ती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरतें और विभिन्न उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिनकी पूर्ति कर पाना सामर्थ्य से परे हो जाता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए सर्वाधिक जरूरी यही है कि घोर निर्धनता में जी रहे ऐसे लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों के महत्व के बारे में जागरूक करने की ओर खास ध्यान दिया जाए क्योंकि जब तक इस कार्यक्रम में इन लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

देश में जनसंख्या वृद्धि का मुकाबला करने के लिए पिछले काफी समय से कुछ कड़े कानून बनाने की मांग हो रही है लेकिन इस दिशा में कुछ राज्य सरकारें दो से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को सरकारी नौकरी तथा स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारी से अयोग्य अघोषित करने जैसे जिस तरह के उपायों पर विचार कर रही हैं, उन्हें किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। हालांकि जनसंख्या वृद्धि मौजूदा समय में गंभीर चुनौती है लेकिन ऐसे उपायों को संवैधानिक नजरिये से भी तर्कसम्मत नहीं माना जाता। चीन में 1980 से पहले केवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमति थी, जिसका उल्लंघन करने पर दम्पति को न केवल सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाता था बल्कि सजा भी दी जाती थी लेकिन वहां यह नीति सफल नहीं हुई। इसीलिए चीन सरकार ने 2016 में इस नीति में बदलाव कर दो बच्चों की अनुमति दी और बाद में तीन बच्चों की अनुमति देनी पड़ी। चीन की तानाशाही सरकार द्वारा नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए दम्पतियों को तीन बच्चे करने की अनुमति क्यों दी गई, इसके कारण समझना भी जरूरी है। दरअसल वहां लोगों की सामान्य प्रजनन दर में निरन्तर गिरावट आ रही है और विशेषज्ञों के मुताबिक यही स्थिति भारत में भी होनी है।

जनसंख्या में स्थायित्व और कामकाजी युवाओं की स्थिर संख्या के लिए महिलाओं की सामान्य प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए और चीन में यह दर निरन्तर गिर रही है। 1970 में चीन में यह दर 5.8 थी, जो 2015 में घटकर 1.6 और 2020 में केवल 1.3 ही रह गई जबकि बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ती गई। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स (एनबीएस) के अनुसार आने वाले समय में आबादी में अधिक उम्र वालों की संख्या बढ़ने से संतुलित विकास और जनसंख्या को लेकर दबाव बढ़ेगा। 1982 में हुई जनगणना में चीन की जनसंख्या में 2.1 फीसदी की सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी लेकिन उसके बाद जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जिसके लिए वहां की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा अपनाई गई दशकों पुरानी 'वन चाइल्ड पॉलिसी' को जिम्मेदार माना जाता है। विगत एक दशक में चीन की जनसंख्या करीब सात करोड़ बढ़ी है लेकिन बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से चीन के लिए अलग ही समस्या उत्पन्न होने लगी है। दरअसल चीन को आशंका है कि अगले दस वर्षों में उसकी जनसंख्या में गिरावट आएगी, जिससे कामगारों की संख्या में कमी आने से उसकी खपत भी घटेगी। एनबीएस के आंकड़ों के मुताबिक चीन को जिन जनसांख्यिकीय संकट का सामना करना पड़ा था, वह और गहरा होने की उम्मीद थी, इसीलिए चीन को अपनी जनसंख्या नीति में बदलाव करने पर विवश होना पड़ा। वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद चीन को विगत सात वर्षों में दो बार अपनी जनसंख्या नीति में बड़ा परिवर्तन करना पड़ा। इसलिए टू चाइल्ड पॉलिसी जैसे कानूनों के जरिये जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों को व्यावहारिक नहीं माना जा रहा बल्कि इसके लिए डराने–धमकाने वाले कानूनों के बजाय लोगों में जागरूकता पैदा किया जाना सबसे जरूरी है।

मनुष्य की विनम्रता और साहस सबसे बड़ा मनोबल

कठिन तथा विषम परिस्थितियों में मनुष्य को अपने मनोबल को सदैव विनम्रता,संयम और साहस के साथ ऊंचा रखना चाहिए।अपने द्वारा की गई मेहनत पर विश्वास एवं निरंतरता रखनी होगी। तब जाकर ही जीवन में सफलता के पल आपके सामने आएंगे स निराशा, हताशा और हीन भावना को कठोर श्रम के बलबूते पर ही विजय प्राप्त की जा सकती हैस

जीवन में उतार–चढ़ाव, कठिन समय और विषम परिस्थितियां आती ही रहती हैंस संकट का समय विषम परिस्थितियां जीवन के अलग–अलग पहलू हैं ।इनसे जूझ कर जो आगे बढ़ता है, वह उच्च मनोबल वाला साहसी व्यक्ति होता है। व्यक्ति के जीवन में साहस, उच्च मनोबल ही सफलता की कुंजी है। जिस भी व्यक्ति ने विषमताओं में रास्ता निकलने का साहस करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है वही सफल हुआ है। हमेशा सफलता का मूल आत्मविश्वास, कठिन श्रम और उच्च आदर्श वाले व्यक्ति की प्रेरणा ही सफलता दिलाने वाली होती है। मनुष्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में मन से हार नहीं माननी चाहिए। उसे सदैव प्रयासरत रहकर परिश्रम तथा जुझारू पन से हर परिस्थिति का सामना कर सदैव अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते रहना चाहिए। मनुष्य को अपनी हर हार, हर पराजय से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए एवं इससे अनुभव प्राप्त कर फिर से खड़ा होने एवं उस पराजित मनोदशा से छुटकारा पाकर फिर से लड़ने की ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, यह सफलता का बड़ा मंत्र है। सर्वप्रथम मनुष्य अपने मनोबल से किन्हीं भी परिस्थितियों को जीतने का साहस रखता है, इसीलिए मनोबल मनुष्य की पहली आवश्यकता है। मनोबल ही साहस को जन्म देता है और साहस, आत्मबल को और आत्मबल से ही मनुष्य किन्हीं भी परिस्थितियों से जूझना एवं टकराने की क्षमता पैदा करता है। जब मनुष्य के पास खोने के लिए कुछ ना हो तो वह निश्चिंत होकर साहस, क्षमता एवं संयम से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है की पीछे पलट कर उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, शिवाय आगे बढ़ने एवं सफलता के लिए अग्रसर होने के। मनुष्य का मनोबल एवं दृढ़ प्रतिज्ञा ही मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। मनुष्य के जीवन का एक तथ्य और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है सकारात्मक सोच, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की ओर उत्साहित करती रहती है। सकारात्मक सोच एवं किसी भी परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लाने की सुनियोजित योजना मनुष्य में आशाओं को भर देती है एवं परिस्थितियों को चुनौती देने की क्षमता का विकास करती है। यह मनुष्य ही है जो हर परिस्थिति में साहस और मनोबल के दम पर उससे विजय प्राप्त करता है। मनुष्य के जीवन और पशु के जीवन में यही फर्क है कि मनुष्य के पास सोचने के लिए मस्तिष्क होता है और वह उसके सकारात्मक उपयोग के साथ आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। मनुष्य मुस्कुराता, हंसता और खिलखिलाता है। जबकि पशु में मुस्कुराने हंसने की क्षमता नहीं होती, और यही कारण है कि मनुष्य ने विषम परिस्थितियों पर सदैव विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है, वह काफी हद तक सफलता पाने में सफल भी हुआ है। मनुष्य यदि परिस्थितियों में अन्य प्रतियोगिताओं में, खेल में, या युद्ध में पराजित होकर भी प्रेरणा लेकर पुनः साहस के साथ पुनःतैयार होता है तो वह आने वाले समय में सफलता का सही हकदार भी होता है, क्योंकि उसने पूरी क्षमता, साहस ,मनोबल के साथ पराजय को स्वीकार कर के उससे कुछ सीखने का प्रयास किया है। अपनी कमियों को दूर करने की हर संभव कोशिश भी की है ।इस तरह वह अगली परीक्षा में जरूर सफल होता है और यही मानव जीवन का सफल अध्याय भी होता है। कुल मिलाकर परिस्थितियां तथा घटनाएं ,दुर्घटनाएं मनुष्य को परिस्थितियों के सामने पराजित करने, झुकाने की कोशिश करती हैं किंतु मानव अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक एवं मानसिक आत्मबल से उसे सफलता में बदल देता है। अनवरत प्रयासरत व्यक्ति अपने साहस परिश्रम से हर चुनौतियों का सामना कर परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर अपने जीवन को सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। जीवन में कठिन परिस्थितियों से जूझ कर जो मानव सदैव सफल होता है वह पूरे समुदाय और समाज के लिए एक प्रेरणादाई व्यक्तित्व बन कर पूरे समाज एवं देश को मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

इसीलिए मनुष्य को किन्हीं भी परिस्थितियों में, खासकर विषम परिस्थितियों में अपने मनोबल और साहस को त्यागना नहीं चाहिए। उच्च मनोबल और साहस की ऊर्जा ही मनुष्य को नई दिशा, नए प्रकाश पुंज की ओर अग्रसर करती है।

अनावश्यक टकराव

हाल के वर्षों में देश के कई राज्यों में राज्य सरकारों व राज्यपालों के बीच गहरे टकराव के मामले प्रकाश में आए हैं। विडंबना यह है कि ये मामले उन राज्यों में सामने आए जहां गैर–राजग सरकारें कार्यरत हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक व तमिलनाडु के बाद हालिया विवाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार व पंजाब के राज्यपाल के बीच है। यह विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि राज्यपालों को आत्मावलोकन करना चाहिए। जाहिर है विसंगतियों के हालात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस गरिमामय संवैधानिक पद के अनुरूप गरिमामय टिप्पणी ही की है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे मामले अदालत में पहुंचें उससे पहले राज्यपाल को मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब में लंबे समय से भगवंत मान सरकार व राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव चला आ रहा था। दरअसल, राज्यपाल ने तीन धन विधेयकों को मंजूरी देने से मना कर दिया था। हालांकि, बाद में एक नवंबर को दो विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले भी राज्यपाल ने पिछले महीने बुलाए गये पंजाब विधानसभा के सत्र को अवैध तक बता दिया था। इस मामले में शीर्ष अदालत में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्यपालों को मामला कोर्ट आने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। यह परिपाटी खत्म होनी चाहिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट आने पर राज्यपाल कार्रवाई करेंगे। यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने राज्यपालों को आत्मावलोकन की जरूरत बताते हुए नसीहत दी कि उन्हें पता होना चाहिए कि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। जाहिर है कि कोर्ट का सीधा अभिप्रायरू है कि माननीय कहे जाने वाले राज्यपाल पद की मर्यादा के अनुरूप ही व्यवहार करें। विडंबना ही है कि हाल के वर्षों में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपाल केंद्र में सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते देखे गए हैं। निस्संदेह, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिये विडंबना ही कही जाएगी कि राज्यपाल किसी राज्य सरकार के कार्यों में बाधा डालें व कैबिनेट के फैसलों को अनुमति देने में आनाकानी करें। राज्यपाल का काम किसी भी राज्य को किसी भी तरह के संवैधानिक संकट से ही बचाना होता है। वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं ताकि राज्य के विकास के कार्य सुचारू रूप से चलाए जा सकें। मगर यदि वे सरकार बनाने व गिराने के खेल में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से राज्यपाल के पद को आंच आएगी। महाराष्ट्र में राजनीतिक विद्रूपताओं के चलते उत्पन्न अस्थिरता के दौर में राज्यपाल की भूमिका को लेकर तीखे सवाल उठे और मामला शीर्ष अदालत तक भी पहुंचा था। ऐसा ही टकराव पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के शासन के दौरान भी नजर आया था। विडंबना यही है कि राज्यपाल के पद पर समाज के विद्वानों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नियुक्त करने के बजाय रिटायर राजनेताओं को बैठाने का खेल दशकों से जारी है। इस खेल में भाजपा से लेकर कांग्रेस तक कभी पीछे नहीं रहे। जिसके चलते वे पद पर बैठते ही अपने पर 'कृपा करने वाले दल' की निष्ठाओं को निभाने के लिये संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करने लगते हैं। फिर चुनी हुई सरकार से टकराव की खबरें सूचना माध्यमों में तैरने लगती हैं। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं किसी भी लोकतंत्र के लिये शुभ संकेत नहीं कही जा सकतीं। वहीं दूसरी ओर पंजाब के राज्यपाल की ओर से शीर्ष अदालत में उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील थी कि राज्यपाल ने उनके पास भेजे गए विधेयकों पर कार्रवाई की थी। साथ ही यह भी कि पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका एक अनावश्यक मुकदमा है। बहरहाल, राज्यों व केंद्र सरकारों के मध्य एक पुल का काम करने वाले राज्यपाल को राज्य के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही जनता द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा उठाये गये कदमों को संबल देना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र राज्यपालों से नीर–क्षीर विवेक के साथ दायित्व निभाने की अपेक्षा करता है।

नरसंहार के एक महीने

इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग को पूरे एक महीने हो गए हैं। पिछले महीने यानी 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया था और इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिना देर किए युद्ध का शंखनाद कर दिया था। उन्होंने अपनी प्रशासनिक और खुफिया असफलता के लिए इजरायल के लोगों से माफी मांगना जरूरी नहीं समझा, न ही उन्होंने इन सवालों की परवाह की कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इस हमले की जानकारी क्यों नहीं जुटा पाई, किस तरह हमास इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने इजरायल पर भीषण हमला बोल दिया। नेतन्याहू इन सवालों की पड़ताल करने के लिए पहले वक्त निकालते, तो शायद ऐसा नरसंहार नहीं होता, जो इस वक्त हो रहा है। तब शायद हमास के असली इरादे पता चलते और ये भी मालूम होता कि आखिर हमास ने इतनी ताकत और दुस्साहस किसके बूते जुटा लिया। लेकिन शायद नेतन्याहू को युद्ध के मैदान में उतरने की हड़बड़ी थी ताकि हमास के बहाने फिलिस्तीनियों को पूरी तरह खदेड़ कर अपना कब्जा स्थायी कर लिया जाए। जिस हमास को खत्म करने की कसम खाकर नेतन्याहू ने युद्ध शुरु किया, वो अब भी बरकरार है। शायद हमास का अमृतकुंड किसी इजरायली बंकर में ही छिपा हो और इसलिए वो खत्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके नाम पर अब तक 10 हजार से अधिक फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं। इनमें 6 हजार से अधिक बच्चे हैं। इन बच्चों में भी बहुत से ऐसे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक साल भी पूरा नहीं किया, कुछ बच्चों को तो मां के पेट में ही इजरायल ने खत्म कर दिया, मानो उन अजन्मी संतानों में हमास का आतंकी रूप इजरायल को नजर आता है। खून, धूल, बारूद की गंध से लिपटे, रोते–बिलखते, डर से कांपते बच्चों की तस्वीरें और वीडियो देखकर किसी भी सामान्य इंसान की रूह कांप जाए। लेकिन युद्धोन्माद में कोई सामान्य कहां रह पाता है। इजरायली सैनिक अपने आका का हुक्म बजा रहे हैं और इजरायल अपने आका अमेरिका की फरमाबरदारी कर रहा है। बिना इस बात की परवाह किए कि उसके हाथों में इतना खून लग चुका है, जिसके दाग सदियों तक बरकरार रहेंगे। आज इजरायल ने इतने फिलिस्तीनी नागरिकों को मारा, जिनमें इतने बच्चे, इतनी महिलाएं, इतने पत्रकार, इतने सैनिक, इतने डॉक्टर हैं, इजरायल ने आज अस्पताल को तबाह किया, आज राहत शिविर पर बम बरसाए, आज गजा पट्टी तक पहुंचने वाली बिजली, पानी की आपूर्ति रोक दी, आज संचार के साधनों को खत्म कर दिया, ऐसी ही खबरें रोजाना महीने भर से लगातार आ रही हैं। और इन खबरों को देखकर भी अगर हम सामान्य बने हुए हैं, तो फिर ये तय है कि हम मनुष्य कहलाने का हक खो चुके हैं। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीनियों को औसतन दिन में ब्रेड की दो स्लाइस और थोड़े से पानी में गुजारा करना पड़ रहा है। बहुतों को ये भी नसीब नहीं हो रहा है। निश्चित ही अमेरिका, इजरायल और इन देशों का साथ देने वाले तमाम सत्ताधीश आला दर्जे की संवेदनहीनता और क्रूरता दिखा रहे हैं। जिन लोगों को मासूमों की मौत, भूख–प्यास, बीमारी देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो खून की नदियों से धरती को मैला करने में लगे हुए हैं, क्या उन लोगों से न्याय और लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद की जा सकती है। किस तरह से ये तमाम शासनाध्यक्ष दुनिया से आतंकवाद मिटाकर शांति स्थापना का दावा कर सकते हैं, जबकि खुद इनके कृत्य किसी आतंकवाद से कम नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अमेरिका, इजरायल और उनका साथ देने वाले तमाम देशों ने बेमानी बना दिया है। संरा महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बार–बार शांति की अपील कर रहे हैं। मानवीय आधार पर युद्धविराम की बातें कर रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी तमाम देशों में लगातार आम जनता फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठा रही है। खुद इजरायल की जनता नेतन्याहू की युद्धनीति का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आई है। लेकिन फिर भी इजरायल युद्धविराम के लिए तैयार नहीं है और उधर जो बाइडेन कह रहे हैं कि पूरे युद्धविराम की जगह मानवीय जरूरत के लिए छोटे विराम लिए जाएं। इस तरह के बयानों से अमेरिका की असली नीयत समझ आ जाती है। मानवीय जरूरत तो यही है कि किसी भी हाल में युद्ध तुरंत बंद हो और नरसंहार पर रोक लगे। छोटे विराम जैसा कोई विकल्प होना ही नहीं चाहिए। मगर युद्ध रुका तो नेतन्याहू के फिलिस्तीन पर कब्जे के मंसूबे धरे रह जाएंगे। इसलिए अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इजरायल युद्ध किए जा रहा है और अमेरिका अपनी मदद जारी रखे हुए है। दुनिया भर के कई राजनेता अपनी सरकारों से अलग राय रखते हुए इजरायल को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मांग उठा चुके हैं। नेतन्याहू पर युद्ध अपराधों का मुकदमा चलाने की मांगे हो रही हैं। यह देखना दुखद है कि इंसानियत के इस मुश्किल वक्त में भारत का नेतृत्व करने वाली मोदी सरकार ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बातचीत की और इसमें दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा के साथ ही फिलिस्तीन के हालात पर भी चर्चा हुई। जिसमें राष्ट्रपति रईसी ने श्री मोदी को पश्चिमी उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के संघर्षच और श्गुट–निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश होनेच की याद दिलाई। रईसी ने कहा, श्आज भारत से उम्मीद है कि वह गजा के बाशिंदों के खिलाफ जायनवादियों के अपराधों को रोकने के लिए अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करे।

ईरान ने मोदी सरकार को भारत के इतिहास और विदेश नीति का वो अध्याय याद दिलाया, जिसके बूते दुनिया में भारत के नाम की साख बनी हुई थी। लेकिन अफसोस कि मोदी सरकार ने सायास उस अध्याय को बंद करने की कोशिश की है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन को औपचारिकता के फ्रेम में जकड़ दिया है और कुछ व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए श्री मोदी इजरायल या अमेरिका के कृत्यों पर खुलकर बोल भी नहीं रहे हैं। इजरायली सरकार के अपराधों पर अमेरिका से लेकर भारत तक का यह ढीला रवैया समूची मानवता के लिए भारी पड़ेगा।

योगी राज में विधायिका पर भारी है यूपी की कार्यपालिका

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल सख्त शासक हैं। उनकी छवि काफी साथ–सुथरी है। करीब साढ़े छहः साल के शासनकाल में योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। यह एक अच्छी बात है। जनता भी ऐसी ही सरकार चाहती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि योगी को छोड़कर यूपी के अन्य सभी राजनेता बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं। सभी दलों में अच्छे–बुरे दोनों किस्म के नेता मौजूद हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का भी यही 'मिजाज' है। यहां भी अन्य दलों की तरह दोनों किस्म के नेता देखने को मिलते हैं। मगर बीजेपी आलाकमान को अपने किसी भी नेता पर भरोसा नहीं है। यहां तक की योगी सरकार के मंत्री भी सरकारी मशीनरी के सामने 'पंख कटे' नजर आते हैं। इसकी वजह है कि बीजेपी में सभी नेताओं को एक ही तराजू में तौला जा रहा है। कहने को तो उसके तमाम नेता जनप्रतिनिधि होने का भी रूतबा रखते हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह से दंतविहीन बना दिया गया है। यह न तो कभी अपने क्षेत्र में पुलिस उत्पीड़न के शिकार लोगों के पक्ष में थाने जा सकते हैं, न शासन–प्रशासन में बैठे अधिकारी उनकी सुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी मशीनरी को आदेश दे रखा है कि यदि कोई बीजेपी नेता उनके पास किसी की सिफारिश लेकर आये तो उसकी बात सुनने की आवश्यता नहीं है, बल्कि अधिकारी अपने विवेक से सही गलत का फैसला लें। यह सब बातें किसी फाइल में तो नहीं कोड की गई हैं, परंतु राजनीति के गलियारों में यह चर्चा आम है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उसके (सपा) सांसद/मंत्री/विधायक आदि जनप्रतिनिधि पुलिस और सरकारी मशीनरी पर दबाव बना लेते थे, वैसा दबाव बीजेपी के जनप्रतिनिधि नहीं बना पाते हैं। होता यह है कि जब भी बीजेपी का कोई नेता किसी सरकारी अधिकारी या पुलिस के पास पहुंचता है तो उसे सीएम योगी का फरमान याद दिला दिया जाता है। या यों कहें उन्हें अपमानित करके वापस भेज दिया जाता है। हालात यह है कि यूपी सरकार के अधिकारी बीजेपी के किसी भी

जनप्रतिनिधि को भाव नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी ऐसे नेताओं से मिलने का टाइम नहीं रहता है। इसको लेकर योगी के पिछले शासन में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा के अंदर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की अपने ही जनप्रतिनिधियों से दूरी हमेशा चर्चा में रहती है। यहां तक की दिल्ली भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में पार्टी के अंदर योगी का कद काफी बढ़ा हुआ है, इसलिए उन्हें कहीं से चुनौती भी नहीं मिलती है। इसी के चलते पीड़ितों व आम लोगों से पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार के मामले तो आए दिन सामने आते रहते हैं। पुलिस अधिकारियों व कर्मियों द्वारा माननीयों से भी अच्छा व्यवहार न किए जाने की शिकायतें बढ़ रही हैं। कहने को तो सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते मिल जाते हैं कि जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान किया जाये। इस बार भी योगी द्वारा माननीयों के प्रति शिष्टाचार व अनुमन्य प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसका असर होते नहीं दिख रहा है।

उत्तर प्रदेश में अफसरशाही के चलते केवल आम आदमी ही नहीं मंत्री सांसद और विधायक भी परेशान हैं। यह लोकसेवक लम्बे समय से कार्यपालिका के चलते होने वाली अपनी परेशानी शिकायतों के रूप में सामने रखते रहते हैं। ज्ञातव्य हो, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इंटीग्रेटेड ग्रीवॉन्स रिड्रेसल सिस्टम लागू कर रखा है, जिसे आइजीआरएस पोर्टल के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई भी सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकता है। इस पोर्टल पर पिछले दो वर्षों में आम जनता के अलावा योगी के कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने भी कार्यपालिका की शिकायत दर्ज कराके अपनी लाचारी सार्वजनिक की है। जिसमें काफी चौंकाने वाली बाते सामने आई है। इन माननीयों की शिकायत से पता चलता है कि प्रदेश में तमाम अफसर आमजन तो दूर मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बात को भी तवज्जो नहीं देते हैं और उनके सुझाए गए कार्यों को बेहद लेटलतीफी करते हैं। इस बारे में नेता और विधायक कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कभी कोई हल नहीं निकल पाया।

गौरतलब हो हाल ही में भी शासन व डीजीपी मुख्यालय द्वारा पुलिसकर्मियों को इसे लेकर निर्देश दिए गये हैं। प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद ने सभी पुलिस आयुक्तों, एसएसपी व एसपी को सांसदों व विधानमंडल के सदस्यों के प्रोटोकाल का अनुपालन कराए जाने को कहा हैं। उन्होंने कहा है कि शासन व संसदीय अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रोटोकाल उल्लंघन के मामले लगातार आ रहे हैं। संजय प्रसाद द्वारा कहा गया है कि सभी अधिकारी सांसदों व विधानमंडल के सदस्यों के सीयूजी नंबर अथवा उनके द्वारा नोट कराया गया अन्य मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अपने मोबाइल में फीड करेंगे तथा काल आने पर उसे रिसीव करेंगे। किसी बैठक में होने अथवा उपलब्ध न होने की स्थिति में काल की जानकारी होने पर प्राथमिकता पर जनप्रतिनिधि को संदेश भेजने के साथ ही काल कर बात करेंगे। जनप्रतिनिधियों द्वारा फोन पर बताए गए प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण कराकर उन्हें जानकारी भी देंगे। इसके साथ ही जिले के अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के मोबाइल पर उनके क्षेत्र के माननीय का फोन नंबर फीड कराएंगे। संजय प्रसाद द्वारा यह भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधि यदि किसी जनहित से जुड़े कार्यों के संबंध में उनसे (अधिकारी व कर्मचारी) से भेंट करते हैं तो उनका सीट से खड़े होकर यथोचित सम्मान किया जाए. इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से वार्ता में यदि उनके अनुरोध अथवा सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हों तो अधिकारी उसके कारणों से जनप्रतिनिधियों को विनम्रतापूर्वक अवगत कराएंगे। किसी अनुचित आचरण अथवा जानबूझकर की गई गलती को दुराचरण माना जाएगा और कार्रवाई होगी. जिलों में प्रोटोकाल से जुड़े मामलों के लिए हर दो माह में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक किए जाने का निर्देश भी दिया गया है,मगर यह आदेश कितना प्रभावशाली रहेगा, इसको लेकर लोगों के साथ–साथ जनप्रतिनिधियों को भी संदेह है। जबकि लोकतंत्र में जरूरी है कि जनप्रतिनिधियों की आवाज को उसके सरकारी नौकर न केवल सुने बल्कि गंभीरता से भी लें, क्योंकि हर जनप्रतिनिधि गलत नहीं होता है। जनता उसे चुनती है और उसे जनता को जबाव देना होता है। जनता की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान जनप्रतिनिधि की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी भी है।

परिषद की कई मांगों पर शासन का सकारात्मक रूख

अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने 15 दिनों में तलब की रिपोर्ट

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मड़ल और अपर मुख्य सचिव कार्मिक के मध्य हुई वार्ता में कई मांगों पर शासन का सकारात्मक रहा। अपर मुख्य सचिव ने परिषद की कई मांगों पर सम्बंधित विभागों से 15 दिनों में रिपोर्ट तलब करने के तत्काल निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव, कार्मिक देवेश चतुर्वेदी के साथ न्याय, चिकित्सा, पंचायती राज, वित्त, शिक्षा आदि के विभागीय अधिकारीगण तथा परिषद के शिष्ट मण्डल में अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी, महामंत्री शिवबरन सिंह यादव, का. अध्यक्ष इं. एन.डी. द्विवेदी अपर महामंत्री डा. नरेश कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह उपाध्यक्ष संतोष तिवारी द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ.प्र.की कर्मचारी समस्याओं के निस्तारणार्थ बैठक अपर मुख्य सचिव कार्मिक श्री देवेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपरान्त परिषद के शिष्ट मण्डल द्वारा बताया गया कि परिषद के मांग–पत्र पर विभागवार संवर्गो की सेवा सम्बन्धी समस्याओं पर विस्तार से विचार मंथन किया गया। विभागीय विवाद समाधान फोरम को क्रियाशील बनाने में न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ न्यायालयी प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के उपायो पर विचारध्विशर्म किया गया, अप्रैल, 2005 से पूर्व विज्ञापित किन्तु बाद में सेवा में आने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवा की भांति पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने पर वित्त विभाग के अधिकारियों के मंत्रण हुई तय हुआ कि महानिदेशक बेसिक शिक्षा के विस्तृत चर्चा के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर सहमति बनी। पंचायती राज सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाये जाने तथा तीन पदोन्नति पर गहन विचार विमर्श के उपरान्त पंचायती राज विभाग को विचार कर पुनः प्रस्तुतीकरण पर सहमति बनी, कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था का लाभ प्रदेश भर में एक समान दिलाये जाने, भुगतान आदि पर विलम्ब पर चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया जायेगा। अंशदायी पेंशन व्यवस्था के अन्तर्गत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकोंध्शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था के अन्तर्गत लाने हेतु चिकित्सा विभाग को समयबद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य के बार–बार निर्देशों के उपरान्त भी विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित बैठके न करने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई। पुनः मुख्य सचिव स्तर से 15 दिनों के भीतर बैठके करके रिपोर्ट मांगे जाने पर सहमति बनी। रोके गये भत्तों आदि पर विचार विमर्श कर शीघ्र निर्णय का आश्वासन दिया गया।

राष्ट्रपति को संयुक्त युवा मोर्चा ने भेजा पत्र

रोजगार संकट हल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की अपील

लखनऊ। संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम सदस्य व युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर रोजगार संकट हल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की अपील है। प्रेषित पत्र में देश भर में एक करोड़ खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को तत्काल भरने, रोजगार अधिकार गारंटी कानून बनाने, आउटसोर्सिंग व महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक और रोजगार सृजन के लिए कारपोरेट्स पर संपत्ति व उत्तराधिकार कर लगाने का मुद्दा उठाया गया। प्रेषित पत्र में रोजगार के लिए शांतिपूर्ण ढंग आंदोलन करने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दमन करने का भी जिक्र किया गया है। संज्ञान में लाया गया कि महज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए पत्र लिखने पर संयुक्त युवा मोर्चा व युवा मंच के पदाधिकारियों को 29–30 अक्टूबर की रात में गिरफ्तार किया गया। इसी तरह इविवि में छात्रों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकार

के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन पर दमन जारी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी प्रोपेगैंडा से उलट सच्चाई यह है कि बेरोजगारी चरम पर है। उच्च शिक्षित युवा 5–7 हजार की कैजुअल नौकरी पाने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। कारपोरेट्स द्वारा प्रदेश में पूंजी निवेश का दावा महज प्रोपेगैंडा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का हश्र देखा जा चुका है। तकरीबन हर सेक्टर में रोजगार के अवसरों में भारी गिरावट आई है। स्थिति यह है कि बैंकों में नागरिकों का पूंजी का भी बड़ा हिस्सा अन्य राज्यों में चला जाता है। युवाओं के पलायन में भी तेजी से वृद्धि हुई है।

डायल112: धराना दे रही महिला कर्मियों के खिलाफ एक्शन, हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सहायता डायल–112 सेवा में संविदा पर काम कर रहीं महिला कर्मचारियों पर सरकार ने सख्त रुख अपना है। दरअसल, धरना दे रही महिला कर्मियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि महिला कर्मियों ने अपात काल सेवाओं को बाधित, सरकारी आदेश का उलंघन किया है। बिना अनुमति धरना देना जैसे मामले में केस दर्ज किया है। बता दें कि अपनी बिभिन्न मांग को लेकर महिला कर्मी धरना दे रही थी। 112 सेवा में संविदा पर कार्य कर रही महिलए सीएम योगी से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाहती थी। लेकिन पुलिस ने उन्हे रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वे लोग मुख्यमंत्री से मिलकर यह शिकायत करना चाह रहे हैं कि पिछले सात वर्षों में उनके वेतन में वृद्धि नहीं की गयी । पुलिस को प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी, बाद में उनमें से कई को हिरासत में लिया गया और जबरन पुलिस बसों में बैठाया गया। एक कर्मचारी हर्षिता ने कहा, हम मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतन ईआरएस 11,800 से बढ़ाकर 18 हजार रुपये किया जाए क्योंकि हम पिछले सात वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और कोई वृद्धि नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि वे लोग पिछले 24 घंटों से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई भी उनकी शिकायतें सुनने नहीं आया है। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, ष्इस बार हमें ऑफर लेटर भी नहीं दिया गया है। अब नई नियुक्तियां की जा रही हैं जोकि हमारे साथ अन्याय है। इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर राज्य के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मांगों पर गौर करके उचित कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने कहा, हम उचित मुद्दों पर कार्रवाई करेंगे। वे हमारे कर्मचारी हैं। उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। इस बीच, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। यादव के शासनकाल में डायल–100 की शुरुआत की गई थी। डायल–100 सेवा को बदलकर अब डायल–112 कर दिया गया है। यादव ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर मंगलवार लिखा, अब सुनने में आया है कि 'डायल 100 का ठेका भी पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल की तरह किसी 'प्रिय पार्टनर को दिया जा रहा है। इसी पोस्ट में उन्होंने महिलाओं के विरोध प्रदर्शन और उन्हें हिरासत में लिए जाने को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर तंज कसते हुए कहा महिलाओं को आरक्षण देने की बात करने वाले उन्हें हिरासत में ले रहे हैं। कहीं नाम बदलने वालों ने 'आरक्षण का नाम 'हिरासत तो नहीं कर दिया है।

शिया कालेज में लैक्मे एकेडमी की ओर से कैरियर काउंसलिंग प्रोगाम आयोजित

लखनऊ। शिया महाविद्यालय में लैक्मे पावर्ड कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम पावर्ड बाय ऐपटेक की ओर से 'के' हाल में प्रातः 11:00 बजे से आयोजित किया गया। लैक्मे की डायरेक्टर सदफ हैदर ने छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ–साथ बच्चों को इस तरह कोर्स से प्रोफेशनल कैरियर बनाकर उज्जवल भविष्य बनाया जा सकता है। लैक्मे की टीम ने छात्राओं को इस कोर्स करने व उससे व्यावसायिक क्षेत्र में कैसे कैरियर बनाया जाए से सम्बंधित प्रोग्राम को दिखाया और फेस व स्कीन से सम्बंधित किस प्रोडेक्ट को कब और कैसे इस्तेमाल करे की जानकारी लैक्मे विशेषज्ञ ने दी। लगभग 400 से अधिक छात्राओं को इस प्रोग्राम के प्रति उत्साह को देखते हुए लैक्मे एकेडमी की डायरेक्टर ने घोषणा की कि शिया महाविद्यालय कि जो छात्राएं इस कोर्स में पंजीकृत होगी। उन्हें एकेडमी की ओर से कोर्स फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही प्रो0 जरीन जहरा रिजवी इंचार्ज (गर्ल्स सेक्शन) ने अपने सम्बोधन में लैक्मे व ऐपटेक की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया कि इस तरह के प्रोग्राम शिया महाविद्यालय में आयोजित किया। प्रोफेशनल ब्यूटी कोर्स पढ़ाई के साथ–साथ भी किया जा सकता है। बदले वक्त के साथ ब्यूटी के क्षेत्र में कैरियर बनाकर रोजगार भी छात्राओं को मिले यही सरकार और महाविद्यालय प्रबंधक संघ की कोशिश है। प्राचार्य प्रो0 एस.एस. रजा बाकरी ने बच्चों से कहा कि इस तहर के ब्यूटी प्रोफेशनल कोर्स प्रोग्राम महाविद्यालय में पहली बार आयोजित हो रहा है। जिससे छात्राओं को ब्यूटी कॉस्मेटोलॉजी क्षेत्र में कैरियर में बना सकेगी। लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय ऐपटेक प्रोग्राम का संचालन महाविद्यालय में पढ़ रही बी.ए. की छात्रा एलिस रिजवी ने किया। इस प्रोग्राम में डॉ0 नगीना बानो, डॉ सीमा राना, के साथ–साथ गर्ल्स सेक्शन की अध्यापिकाएं शामिल हुई।

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने कोर्ट में किया सरेंडर, तीन मामलों में जारी था गैरजमानती वारंट

लखनऊ। तीन मामलों में फरार चल रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने आज यानि बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में

सरेंडर कर दिया। तीनों मामलों में उमर अंसारी के विरुद्ध कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी था। फिलहाल एसीजेएम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि पहले मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी।पुलिस ने विवेचना मे मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि मे सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्दाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है।

औरैया मामले में डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान, सीएचसी अधीक्षक और उक्त प्रकरण से संबंधित डॉक्टरों को हटाने का दिया आदेश

लखनऊ। औरैया जिले के बिधूना सरकारी अस्पताल के वायरल वीडियो पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। उन्होंने सीएचसी अधीक्षक और उक्त प्रकरण से संबंधित डॉक्टरों को हटाने का आदेश दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। दरअसल स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में एक भाई अपनी बहन के शव को पीठ से बांधकर बाइक से घर ले जाता दिखा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। जिस पर अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्शन लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर कहा कि जनपद औरैया के सीएचसी, बिधूना में शव को पीठपर बांधकर बाईक से ले जाने संबंधी वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा सीएचसी, अधीक्षक व उक्त प्रकरण से संबंधित डॉक्टरों को भविष्य के लिए एक–एक प्रतिकूल प्रवष्टि देकर तत्काल वहाँ से हटाये जाने के आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औरैया को दिये गए हैं तथा साथ ही सभी सीएचसी, पीएचसी को मरीजों के लिए एंबुलेंस सुविधा की सुनिश्चितता करने हेतु आदेश निर्गत किए जाने के भी आदेश दिये गए हैं। बता दें कि घटना जिले के बाबूराम मोहनलाल महाविद्यालय के पास स्थित नवीन बस्ती पश्चिम की है। जहां के निवासी प्रबल प्रताप सिंह की बेटी अंजलि (20) नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए कमरे में गई। उसने बाल्टी में पानी भरकर रोड लगाई थी। इसी दौरान अचानक वह करंट की चपेट में आ गई और बेहोश होकर वहीं गिर गई। जब अंजलि के परिजनों ने उसे जमीन पर गिरा हुआ देखा तो उसी वक्त उसको लेकर बिधनू में सीएचसी पहुंचे। अस्पताल में डाक्टरों ने अंजलि को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अंजलि के घरवालों ने शव को बिना पोस्टमार्टम के घर ले जाने की बात कहकर अस्पताल से बाहर निकल आए। सीएचसी के बाहर अंजलि का भाई आयुष बाइक पर बैठा और उसकी दूसरी बहन पीछे बैठ गई। फिर उनके पिता ने बीच में अंजलि की लाश रख दी। इसके बाद आयुष दुपट्टे से अंजलि के शव को पीठ पर बांध लिया। काफी समय तक अस्पताल के बाहर ये सब चलता रहा और सीएमसी का स्टाफ वहां खड़ा तमासगीर बने रहे।

ओलेक्स पर बिक्री के लिए झूला बेचना पड़ा महंगा,

ठगों ने लगा दी 3 लाख 28 हजार रूपये की चपत

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को ओलेक्स पर घर का सामान बेचना महंगा पड़ गया। साइबर जालसाजों ने सामान के पैसे की जगह उल्टा अपने ही खाते में कई बार में लाखों रूपये ट्रांसफर करवा लिया। पीड़ित ने ठग के मोबाइल नंबर पर फोन मिलाया तो स्वीच ऑफ मिला जिसके बाद उसने ऑनलाइन साइबर सेल में शिकायत करने के बाद आशियाना कोतवाली में ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया हैं। आशियाना क्षेत्र के रतन खंड में रहने वाले संतोष कुमार द्विवेदी के मुताबिक, उन्होंने अपने घर का झूला बेचने के लिए ओलेक्स पर डाला था ,बीते 5 नवम्बर को उनके फोन पर एक कॉल आई और फोन करने वाले ने अपना परिचय संजय कुमार बताया और झूले को खरीदने की मंशा व्यक्त करते हुए 6800 रूपये में झूले का सौदा तय किया। पैसा ट्रांसफर करने के लिए उनका एकाउंट डिटेल मांगा और कहा कि वह ऑनलाइन उनके खाते में पहले एक रूपये फिर सारे पैसे ट्रांसफर कर रहा है। जिसकी पुष्टि वह कर दे, लेकिन पैसा उनके खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ तो उन्होंने कालर को बताया तो कालर ने कहा कि उनका बिजनेस एकाउंट है। इसलिए पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। आप पहले मुझे पैसा ट्रांसफर करे फिर वह सारे पैसा ट्रांसफर कर देगा और इस तरह कालर कई बार में कुल तीन लाख 28 हजार रूपये ट्रांसफर करवा लिए और उनका खाता भी खाली हो गया लेकिन जालसाज ने उन्हें पैसा ट्रांसफर नहीं किया और अपना मोबाईल फोन भी बंद कर दिया। अपने संग ठगी का एहसास होने पर पीड़ित खाताधारक ने ऑनलाइन साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा स्थानीय थाना आशियाना पर लिखित शिकायत की है। आशियाना इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई हैं।

टीन सहित गिरी पक्की दीवार, कबाड़ी की मौत, रेस्क्यू के दौरान दो फायरकर्मी भी हुए घायल

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में स्थित स्कूटर इंडिया चौराहे के पास बुधवार तड़के करीब साढ़े चार बजे एक टीन सेड नुमा दीवार भरभरा कर गिर गई। जिससे टीन के नीचे सो रहा एक 55 वर्षीय व्यक्ति दब कर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर लखनऊ सीएफओ और सरोजनीनगर फायर स्टेशन प्रभारी सुमित जादौन टीम के साथ पहुंच गए और कड़ी मशक्कत कर दीवार के नीचे दबे व्यक्ति को बाहर निकाल कर एंबुलेंस की मदद से लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया। जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान रेस्क्यू कर रहे दो फायरकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार करने के बाद छुट्टी दे दी गई। हालांकि दीवार गिरने का सही कारण पता नही चल सका हैं। मूल रूप से गोंडा जनपद के रहने वाले दीन दयाल कश्यप (53) पत्नी रीता कश्यप और तीन बेटे गोविंद ,सत्यम,गौरव और बेटी सुकन्या के साथ चारबाग में स्थित मोहन होटल के पास किराए पर रह कर कबाड़ी की दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। वह अपनी कबाड़ी की दुकान सरोजनीनगर थाना क्षेत्र के स्कूटर इंडिया चौराहे के पास खोल रखे थे, जिसमें वह अकेला निवास करता था, उसका बाकि परिवार चारबाग में रहता है। मौत की खबर सुनते परिजनों में कोहराम मच गया हैं। रेस्क्यू के दौरान फायरकर्मी चालक रजपाल पंकज व फायरमैन रोहित कुमार भी घायल हो गए हैं। सरोजनीनगर फायर स्टेशन प्रभारी सुमित जादौन ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 4.20 बजे, फायर स्टेशन सरोजनी नगर कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि स्कूटर इंडिया चौराहा के पास दीवार के नीचे एक आदमी दब गया है। सूचना मिलते ही वह रेस्क्यू टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे।

लखनऊ पहुंचे अभिनेता धर्मेंद्र, पहली बार राजधानी में करेंगे फिल्म इक्कीस की शूटिंग

लखनऊ। भारतीय सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र बुधवार को लखनऊ पहुंचे। वह अगले 10 दिन तक राजधानी में रहेंगे। बताया जा रहा है कि वह अपनी फिल्म इक्कीस की शूटिंग करेंगे। धर्मेंद्र पहली बार लखनऊ में किसी फिल्म की शूटिंग करेंगे। अपने छह दशक के कैरियर में धर्मेंद्र ने करीब 200 फिल्मों में काम किया। लेकिन लखनऊ में वह पहली दफा शूटिंग करेंगे। 87 साल के धर्मेंद्र फिर से फिल्मों में सक्रिय हुए हैं। धर्मेंद्र इससे पहले करण चौहर की फिल्म रॉकी और रानी में नजर आए थे। इसमें उन्होंने शबाना आजमी, जया बच्चन, रणबीर सिंह और ऑलिया भट्ट जैसे कलाकरों के साथ काम किया था। बुधवार चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। यह फिल्म परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी से प्रेरित है। फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन करेंगे। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ एक और बड़े स्टार परिवार के बेटी की एंट्री सिनेमा जगत में हो रही है। इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी नजर आएंगे। अगस्त्य अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा और निखिल नंदा के बेटे हैं। अगस्त्य का संबंध कपूर परिवार से भी है। इनकी दादी राजकपूर की बेटी है। ऐसे में बच्चन और कपूर परिवार

की एक और पीढ़ी फिल्मों में नजर आने वाली है। बताया जा रहा है कि अगस्त्य ने इस फिल्म के लिए वरुण धवन को रिप्लेस किया है। यह पहला मौका होगा जब धर्मेंद्र शहर में शूटिंग करेंगे। हालांकि, 60 के दशक में उनकी फिल्म ममता की यहां शूटिंग की जा चुकी है। उस दौरान नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान में एक सीन फिल्माया गया था, जिसमें अभिनेत्री सुत्रिता सेन बाघ के बाड़े के पास गोद में बच्ची को लिए होती हैं, जो कि बाघ की दहाड़ से घबरा जाती है। इस फिल्म का कुछ हिस्सा पुराने लखनऊ में भी कैमरे में कैद किया गया था। वहीं, धर्मेंद भले ही लखनऊ में शूटिंग ना कर गए हों लेकिन उन्होंने अपनी एक फिल्म में खदरा के लिए रहने वाले मुबीन की स्कूटर जरूर चलाई थी। 'इक्कीस'फिल्म स्त्री, लुका–छिपी और मिमी जैसी फिल्में बनाने वाले दिनेश विजान बना रहे हैं। यह उनकी पिछले कुछ महीनों में अदब के शहर में दूसरी फिल्म होगी। उन्होंने यहां कुछ समय पहले अक्षय कुमार, सारा अली खान और निमरत कौर जैसी स्टारकास्ट वाली फिल्म स्काईफोर्स शूट की थी।

ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत, बच्चों का रो–रो बुरा हाल

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के कृष्णागर क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस और स्थानीय पुलिस ने महिला की शिनाख्त करवाने के बाद परिजनों को सूचना दी। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया हैं । पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक,उन्नाव जनपद के थाना औरास के मदारी खेड़ा निवासी कन्हैयालाल पत्नी रामदुलारी (39) और दो बेटों दीपक ,दिलीप व एक बेटी शालिनी के साथ कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के ओशो नगर कालोनी में चक्र चौराहा के पासकिराए पर रहकर मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता हैं तो वही, रामदुलारी घरों में बर्तन धुलने का काम करती थी।

कन्हैया लाल गांव में धान कटवाने गया हुआ था। घर पर राम दुलारी और बच्चे अकेले थे। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह करीब साढ़े चार बजे कनौसी के पास रेलवे लाइन पर रामदुलारी किराना का सामान लेकर रेलवे लाइन पार कर रही थी कि इस बीच अचानक ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

जीआरपी पुलिस ने शव को पोस्मार्टम के लिए भेज दिया था। जंहा पर परिजनों को दोपहर में पोस्मार्टम होने के बाद शव उनके सुपुर्द कर दिया गया । परिजन शव लेकर अपने गांव चले गए। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हैं।

भाजपा सरकार को कांग्रेस को कोसने से फुरसत नहीं : अंगारा

लखनऊ,(यूएनएस)। पंजाब से लेकर बंगाल तक 40 प्रतिशत आबादी की सांसों पर संकट मंडराया हुआ है,देश के लोग भयभीत हो रहे हैं, परन्तु केंद्र सरकार देश के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनकी समस्याओं को न देखकर सिर्फ राज्यों के चुनावों में व्यस्त हैं। समाजवादी विचारक, कायस्थ चित्रगुप्त महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और राजद के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रविन्द्र कुमार श्रीवास्तवश्अंगारा ने कहा कि भाजपा की सरकारें जहां–जहां है सिर्फ उनका कार्य कांग्रेस को कोसने और बदनाम करने में अपना सारा समय व्यतीत करती हैं। भाजपा सरकार को कांग्रेस को कोसने से फुरसत नहीं,इनसे जनहित की उम्मीद नहीं है। विकास और देशवासियों की समस्याओं को निदान करने में शक्ति और दिमाग नहीं लगा रहे हैं। श्री अंगारा ने यह भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा हारने जा रही है। वहां के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत आरोप लगाकर वहां की सरकार को बदनाम कर सत्ता हासिल करने का राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। छत्तीसगढ़ की जनता से अपील करना चाहता हूं, झूठ के षड्यंत्र से दूर रहें और भाजपा जो एक षड्यंत्र कारी पार्टी है, उसे सत्ता से दूर रखें। कांग्रेस को पुनः सत्ता सौपने का कार्य करें। भाजपा ईडी और सभी केन्द्रीय मंत्रियों को चुनाव में झोंक दिया है और देश के नागरिक समस्याओं से पीड़ित हैं दुखी हैं। जनता को अपने विवेक से काम करना चाहिए,मतदान करते समय दूरदृष्टि से चुनाव करें।

6000 शिक्षकों की भी नियुक्ति का रास्ता साफ,

एचसी ने सरकार को 3 महीने में प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश

लखनऊ। प्राथमिक स्कूलों में 2016 में हुई 12460 सहायक शिक्षकों की भर्ती में से बाकी बचे 6470 की नियुक्ति का भी रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने चयनित अभ्यर्थियों को भी भर्ती करने का आदेश दिया है। शून्य जनपद विवाद के कारण मामला लटक गया था। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह फैसला राज्य सरकार व कई अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल 19 विशेष अपीलों को निस्तारित कर सुनाया। कुछ अपीलों में एकल पीठ नवंबर 2018 को भर्ती पर रोक वाले के आदेश को चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2016 की सहायक शिक्षक भर्ती मामले में कहा कि संबंधित प्राधिकारी, एनसीटीई की अधिसूचना और 26 दिसंबर 2016 के सर्कुलर के तहत संबंधित जिलों के सभी पात्र सहायक शिक्षकों की कॉमन मेरिट सूची तीन माह में तैयार कर सभी पदों को भरने का निर्णय लें। दरअसल, साल 2016 में शुरू भर्ती में 75 में से 24 जिलों में एक भी पद खाली नहीं था। इन शून्य खाली पदों वाले जिलों के अभ्यर्थियों किसी अन्य जिले में आवेदन करने की छूट दी गई थी। मार्च 2017 में पहली काउंसिलिंग हुई, लेकिन उसी समय प्रदेश में सरकार बदल जाने के बाद नई सरकार ने 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगा दी थी। इस पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक नवम्बर 2018 को भर्ती पर रोक वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। सभी अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग भी कराई। 51 जिलों के करीब 6000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। लेकिन बाकी चयनितों की नियुक्ति नहीं हो पाई। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों व राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए 19 अपीलें दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट के फैसले व आदेश के बाद शून्य खाली पदों वाले जिले के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

बिरसामुण्डा जयन्ती पर लखनऊ में दिखेगी आदिवासी संस्कृति की झलक

राज्य सरकार जनजातियों के कल्याण के लिए कटिबद्ध : गोंड

देश के 14 राज्य जनजाति गौरव दिवस के आयोजन में करेंगे सहभागिता

लखनऊ,(यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री समाज कल्याण संजीव कुमार गोंड ने कहा है कि जनजाति समाज के लोकनायक बिरसा मुण्डा की 148वीं जयन्ती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में 15 से 21 नवम्बर को भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 14 राज्यों के जनजाति समाज से जुड़ी संस्कृति, संस्कार, परम्पराओं, रीति–रिवाज, खानपान, भेष–भूषा, नृत्य एवं गीत, खेल–कूद तथा विभिन्न शिल्प कलाओं एवं वाद्ययंत्रों का प्रदर्शन संस्कृति नाटक अकादमी लखनऊ में किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन होगा। राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातियों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अलावा जनजाति कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की सहभागिता होगी। कार्यक्रम का शुभारम्भ 15 नवम्बर को शाम 04 बजे से शुरू होगा। लोकनायकबिरसामुण्डा की जयन्ती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले साल घोषणा की गयी थी। उसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा इस समारोह का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों के जनजातीय समूहों के गौरवशाली इतिहास एवं समृद्ध विरासत की झलक मिलेगी। समारोह के माध्यम से आदिवासी समाज की विलुप्त होती आ रही लोक कलाओं को जीवंत बनाने का अनूठा प्रयास किया गया है।प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य मुकेश मेश्राम ने कहा कि लोकनायक बिरसामुण्डा आदिवासी समाज के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और अपने समाज को मुख्यधारा में जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। बिरसामुण्डा आदिवासियों की आवाज बनकर उभरे। उनके संघर्ष एवं योगदान को जीवंत बनाने तथा पूरे देश के आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत को आज की युवा पीढ़ी को परिचित कराने के लिए 15 नवम्बर से 21 नवम्बर तक जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभाग शामिल हैं।प्रमुख सचिव ने कहा कि इस अवधि के दौरान जनजाति बाहुल्य जनपदों के जिलाधिकारियों के निर्देशन में आदिवासी समाज के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। देश के 20 राज्यों के आदिवासियों

को आमंत्रित किया गया था जिसमें से 14 राज्यों ने इस समारोह में भाग लेने की सहमति दी है। इस भव्य आयोजन के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। आदिवासियों के परिधान, शिल्प, नृत्य, गीत संगीत, वाद्ययंत्र आदि का प्रदर्शन किया जायेगा। कार्यक्रम आदिवासियों की विलुप्त होती जा रही संस्कृति को जीवित रखने के लिए है। बलरामपुर के इमिलिया कोडर में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का निर्माण कराया गया है।प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉ हरिओम ने इस अवसर पर कहा कि एक सप्ताह तक चलने वाले जनजाति गौरव दिवस के दौरान आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न आयामों का प्रदर्शन किया जायेगा। इस अवसर पर जनजाति कवि सम्मेलन, खेल–कूद का आयोजन के अलावा परिधान, व्यंजन का प्रदर्शन तथा जनजातीय जीवन की झलक प्रस्तुत की जायेगी। इस कार्यक्रम को संविधान दिवस 26 नवम्बर तक ले जाने का प्रयास किया जायेगा। प्रदेश के कई संस्थान मिलकर इस आयोजन को सफल बनायेंगे। इसमें जनजाति कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की भी भूमिका होगी। इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में मनाया जायेगा। प्रदेश के 19 जनपदों में जनजाति समाज के लोग पाये जाते हैं। संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।इस अवसर पर लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान के निदेशक अतुल द्विवेदी, संस्कृति विभाग व जनजाति विकास विभाग, पर्यटन विभाग के अधिकारी एवं अन्य महानुभाव उपस्थित थे।

एनएसएस द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

अलीगढ़। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इकाई द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। मुख्य अतिथि, एएमयू के विधि संकाय के प्रोफेसर सैयद अली नवाज जैदी ने वित्तीय बैंक धोखाधड़ी कॉल, ओटीपी साझाकरण, क्यूआर कोड के माध्यम से पीड़ितों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों पर चर्चा की। उन्होंने ऑनलाइन उत्पीड़न, ट्रोलिंग और ब्लैकमेलिंग के बारे में भी छात्रों को बताया। सुश्री नीलम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक (साइबर अपराध), अलीगढ़ ने कहा कि अगर किसी को नियमित रूप से फर्जी कॉल या संदेश आते हैं, तो उसे बिना किसी देरी के 1930 पर आपातकालीन कॉल करना चाहिए या बलइमतबतपउम.हवअज.पद पर शिकायत दर्ज कराने चाहिए।समर पाल सिंह, उप–निरीक्षक ने छात्रों को बताया कि कैसे साइबर अपराधी के अपराधी पीड़ित के मोबाइल फोन को स्कैन करने के लिए तकनीक का उपयोग करते हैं और वह इस प्रकार के साइबर अपराधों से खुद को किस प्रकार से सुरक्षित रखें। सुश्री कुसुमलता, उप–निरीक्षक ने अज्ञात वेबसाइटों या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यक्तिगत विवरण साझा न करने की सलाह दी, जबकि सुश्री मनीषा (साइबर अपराध पुलिस अधिकारी) ने छात्रों को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फर्जी आईडी के बारे में जागरूक किया। मुख्य वक्ता, एएमयू के विधि संकाय के सहायक प्रोफेसर डॉ. गौरव वार्ष्णेय ने सर्वेक्षणों के आंकड़ों को साझा किया। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों के शिकार ज्यादातर किशोर, बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के डिजिटल युग में प्रत्येक व्यक्ति को साइबर सुरक्षा का ज्ञान और समझ होनी चाहिए। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉ. तबस्सुम चौधरी, विधि संकाय, एएमयू ने सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पर चर्चा की, जिसमें साइबर अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने मैलवेयर और फिशिंग हमलों जैसे ऑनलाइन साइबर खतरों का एक सिंहावलोकन भी दिया। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. अरशद हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, एएमयू और कार्यक्रम की सह–संयोजक डॉ. सुहालिया परवीन, सहायक प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, एएमयू ने भी इस अवसर पर साइबर अपराध पर कपने विचार स्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन वाणिज्य विभाग में एम.आई.आर. एम. की छात्रा दिव्या शर्मा, द्वारा किया गया। जबकि बी.ए.एल.एल.बी. के छात्र अखिल कौशल ने स्वागत भाषण और धन्यवाद ज्ञापन दिया।

सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारी और अधिकारी नही मनागेंगे दीपावली

मुख्यमंत्री और गन्ना मंत्री को सौपा ज्ञापन

महंगाई भत्ते का भुगतान न होने से खफा

लखनऊ। राज्य सरकार द्वारा जारी देय डीए की शेष आठ फीसदी का भुगतान उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड और चीनी मिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों का अभी तक नही किया गया है जिसके चलते शुगर फेडरेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों में काफी आक्रोश है।राष्ट्रीय चीनी मिल अधिकारी परिषद के तत्वावधान में सहकारी चीनी मिलों और फेडरेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, गन्ना मंत्री,मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग और एमडी शुगर फेडरेशन को आज मांगपत्र देकर अनुरोध के साथ घोषणा की है कि यदि महंगाई भत्ते की बची 08 प्रतिशत किश्तों को दीपावली से पूर्व वेतन में नहीं लगाया जाता तो सहकारी चीनी मिलों और संघ के कर्मचारी और अधिकारी दीपावली नही मनायेंगे। इसका असर आगामी पेराई सत्र में दिखायी पड़ेगा। परिषद के अध्यक्ष एसपी सिंह,उपाध्यक्ष सुधीर सोनकर और महामंत्री कैलाश उपाध्याय ने मुख्यमंत्री और गन्ना मंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर बकाये महंगाई भत्ते को दीपावली पर दिये जाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।

कर्मचारियों ने गन्ना मंत्री को अवगत कराया कि सहकारी चीनी मिलों ने कोरोना काल मे भी रिकार्ड चीनी उत्पादन किया।कर्मचारियों ने कोरोना वायरस की तनिक परवाह नहीं कि।संघ ने गन्ना मूल्य का पूर्ण भुगतान किया, कोई गन्ना मूल्य बाकी नहीं। आज बीस हजार के सापेक्ष करीब दो हजार कर्मचारी व अधिकारी शेष है और आये दिन रिटायरमेंट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ता देने में परेशानी क्यों है।सहकारी चीनी मिलों में प्रतिनियुक्ति पर आए जीएम अफसरों को महंगाई भत्ता समय पर मिल रहा है, संघ और मिल कर्मचारियों के साथ अन्याय क्यों। पूर्व अपर सचिव चीनी उद्योग ने न जाने किस नियम से 01 जनवरी 22 से देय 03 फीसदी महंगाई भत्ता 01 जुलाई 22 से दिया तथा 01जुलाई 22 को देय महंगाई भत्ता 01जनवरी23 से दिया तथा 01 जुलाई 23 से 04 प्रतिशत महंगाई भत्ता जुलाई 24 से दिये जाने का आदेश दिया है।यह न्याय संगत नही है।कर्मचारियों में रोष है, समाधान नही तो फिर दीपावली नही मनायेंगे।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com

R.N.I.-UPHIN/2012/45127

नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।